सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 575
03/08/2017

मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की

पटना, 03 अगस्त :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की। समीक्षा बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित सभी बिन्दुओं पर विस्तृत समीक्षा की गयी। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आर0के0 महाजन द्वारा शिक्षा विभाग का विस्तृत प्रस्तुतीकरण मुख्यमंत्री के समक्ष दिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

समीक्षा बैठक के बाद मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जारी रखते हुये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति का कार्यक्रम भी चालू रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरॉलमेंट रेशियो बढ़ाने का है। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी का गठन कर उसी के माध्यम से दोनों कार्यक्रम (स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति) कार्यान्वित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो गया है। इसके नियमित साफ–सफाई के लिये 53000 विद्यालयों में ओवरहेड टैंक लगवाया जायेगा। इसके लिये राशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, राज्य सरकार की संस्था/निगम अन्तर्गत सी0एस0आर0 फंड से तथा आवश्यकता होने पर मुख्यमंत्री सहाय्य कोष से दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि शौचालय की सफाई के लिये नियमित व्यवस्था विद्यालय द्वारा की जायेगी, इसके लिये स्वच्छता, सफाई रखने का सकारात्मक माहौल बनाया जायेगा, अच्छे कार्य करने वाले विद्यालयों को पुरस्कृत किया जायेगा।

मुख्य सचिव ने बताया कि अब विद्यालय से बाहर मात्र 1 प्रतिशत बच्चे ही रह गये हैं। इनमें अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे एवं आर्थिक–सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़े वर्ग के बच्चे ज्यादा हैं, इन्हें विद्यालय से जोड़ने एवं उम्र के अनुसार शिक्षा के लिये आवासीय शिक्षण की व्यवस्था अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी। उन्होंने बताया कि 947 प्राथमिक विद्यालय जिन्हें भूमि प्राप्त हो गयी है, उनका भवन निर्माण राज्य सरकार के संसाधनों से कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर अच्छी शिक्षा के लिये शीघ्र ही विद्यालयों में ई–लर्निंग की व्यवस्था आरंभ करायी जायेगी। आरंभ में यह कार्य पायलट के रूप में किया जायेगा तथा उसके अनुभव के आधार पर इसे विस्तारित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उच्च विद्यालयों की शिक्षा को बेहतर करने का ठोस प्रयास हो। इसमें शिक्षक नियोजन के लिये केन्द्रीयकृत व्यवस्था बनाई जायेगी। उन्होंने कहा कि जिन शिक्षा पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापक, शिक्षकों का वार्षिक परीक्षा

2017 में खराब प्रदर्शन हुआ है, उन्हें चिन्हित कर दण्डित किया जायेगा एवं सुधार के ठोस कार्यक्रम तीन माह में लागू किया जायेगा।

मुख्य सचिव ने बताया कि अनुदानित विद्यालयों एवं महाविद्यालय जिन्हें अनुदान पूर्व में नहीं दिये गये हैं, उनका भुगतान शीघ्र किया जायेगा। आगे से उन्हें परफॉरमेंस के साथ–साथ आधारभूत संरचना, शिक्षकों की उपलब्धता के साथ जोड़कर राशि देने की व्यवस्था की जायेगी ताकि उनमें शैक्षिक गुणवता आये। उन्होंने कहा कि बिहार बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि बच्चों में बेहतर शैक्षिक प्रगति के लिये मॉडल प्रश्न–पत्र उतर सहित तैयार कर उपलब्ध करायें तथा परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन व्यवस्था को बेहतर करें। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में जहॉ एक ही भवन में दो या दो से अधिक विद्यालय संचालित हैं, उन्हें एक ही विद्यालय में मर्ज किया जायेगा तथा पदस्थापित अतिरिक्त शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरित किया जायेगा।

मुख्य सचिव ने बताया कि चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी के अन्तर्गत 2 अक्टूबर 2017 से 'बापू आपके द्वार' कार्यक्रम को संचालित किया जायेगा तथा सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में गॉधी कथा वाचन आरंभ किया जायेगा।

समीक्षात्मक बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, शिक्षा मंत्री श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव शिक्षा श्री आर0के0 महाजन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा सहित शिक्षा विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

******